कलावती देवी हरलालका

बनाम

आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और अन्य

1 मई, 1967

[जे.सी.शाह, एस.एम. सिकरी और वी. रामास्वामी, जे.जे.]

आयकर अधिनियम, 1961, धारा 297 और 298- आयुक्त द्वारा एस 33 आयकर अधिनियम, 1922 के तहत मूल्यांकन के पुनरीक्षण की सूचना जारी करना। क्या ऐसी कार्यवाहियाँ एस 297 (2) (ए)- धारा 6 सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 एस 298 का प्रभाव और आयकर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1962 की वैधता।

अपीलकर्ता को 24 जनवरी, 1963 को आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल से एक नोटिस मिला, जिसमें एस 33 आयकर अधिनियम, 1922 के तहत उसके आकलन वर्ष 1952-53 से 1960-61 के लिए एक पुनरीक्षण शुरू किया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। जिसमें प्रार्थना की गई कि नोटिस को रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादी को इसे लागू करने से रोका जाए। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी और खण्डपीठ की अपील भी खारिज कर दी गई।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि आयकर अधिनियम, 1922, 1961 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है जो 1 अप्रैल, 1962 को लागू हुआ, प्रतिवादी के पास धारा 33B 1922 के अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने की कोई शक्ति, अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं था। (ii) वह धारा6 सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में कार्यवाही ko शुरु करने को अधिकृत नहीं करता है, क्योंकि 1922 का अधिनियम के

लागू होने के दौरान इसके संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया था। (iii) वह धारा 1961 के अधिनियम की धारा 298 शून्य था और किसी भी घटना में, उस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल उन मामलों के संबंध में किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत सरकार ने आयकर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 1962 को प्रख्यापित किया, जिसके खंड 4 में इस तरह के मामले को शामिल किया गया है, वर्तमान केवल मामलों के संबंध में किया जा सकता है। धारा 297 के तहत निपटाए गए मामले उस अधिनियम की कार्यवाही से संबंधित नहीं है।

अभिनर्धारित किया गया कि: (i) प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही वैध थी क्योंकि वे 1961 अधिनियम की धारा 297(2) के खंड (ए) में "उस व्यक्ति के आकलन के लिए कार्यवाही" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते थे। [841ई:846बी]

"आकलन" शब्द का बहुत व्यापक अर्थ हो सकता है; यह करदाता पर देनदारी का पता लगाने और उसे थोपने की पूरी प्रक्रिया को समझ सकता है। धारा 297 के सन्दर्भ में कुछ भी नहीं था, जिसमें अभिव्यक्ति "मूल्यांकन की प्रक्रिया" को एक संकीर्ण अर्थ देने की आवश्यकता थी। धारा 297 का उद्देश्य उन सभी आकस्मिकताओं के लिए यथासंभव प्रावधान करना है जो 1922 अधिनियम के निरसन से उत्पन्न हो सकती हैं। 1845ए-सी]

आयकर आयुक्त, बम्बई बनाम खेमचंद रामदास, 6 आई.टी.आर. 414 पृष्ठ 423; ए.एन. लक्ष्मण शेनॉय बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम, 34 आई.टी.आर. 275 पृष्ठ 291; सी.ए. अब्राहम बनाम आयकर अधिकारी, कोट्टायम, 41 आई.टी.आर. 425 पृष्ठ 429-430 पर; आयकर आयुक्त बनाम भीकाजी दादाभाई एंड कंपनी, 42 आई.टी.आर. 123 पृष्ठ पर. 127; आयकर आयुक्त बनाम पटियाला सीमेंट कंपनी लिमिटेड, 32

आई.टी.आर. 333; भाईलाल अमीन व संस लिमिटेड, बनाम आर.पी. दलाल, 24 आई.टीआर. 229, संदर्भित।

(ii) सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 लागू नहीं होगी क्योंकि धारा 297(2) कई मामलों के लिए प्रावधान करके इसके विपरीत इरादे का सबूत देती है, कुछ धारा 6 के तहत परिणाम के अनुरूप हैं और कुछ इसके विपरीत परिणाम हैं। [846 ए]

यूनियन ऑफ इंण्डिया बनाम मदन गोपाल काबरा, 25 आई.टी.आर. 58, संदर्भित.

(iii) 1961 अधिनियम की धारा 298 वैध है और वर्तमान मामला सीएल द्वारा कवर किया गया था। आयकर के 4 (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1962। [846 सी-डी]

जालान ट्रेडिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम मिल मजदूर यूनियन। [1966] 11 एल.एल.जे. 546; आयकर आयुक्त बनाम दीवान बहादुर रामगोपाल मिल्स, 41 आई.टी.आर. 280 एवं पंडित बनारसी दास भनोट बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 9 धाराटी.सी. 388, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1421/1966

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 281/1963 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 8 दिसंबर, 1964 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता और हस्तक्षेपकर्ता की ओंर से देबी पाल, आर.के. चौधरी और बी.पी. माहेश्वरी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओंर से डी. नरसाराजू और आर.एन. सच्चे।

न्यायालय का निर्णय सीकरी, जे. द्वारा सुनाया गया।

24 जनवरी, 1963 को, आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने श्रीमती को निम्नलिखित नोटिस भेजा। हमारे समक्ष अपीलकर्ता कलावती हरलालका को इसके बाद निर्धारिती के रूप में जाना जाएगा:

> "विषय: 1952-53 से 1960-61 तक के आयकर आकलन। आकलन गलत और राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल- भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा 33 बी के तहत आकलन का संशोधन- कर अधिनियम 1922 प्रस्ताव संबंधी सूचना।"

कर निर्धारण वर्ष 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60 और 1960-61 के लिए आपके मामले के रिकॉर्ड मंगाने और जांचने पर और अन्य संबंधित रिकार्डों के आधार पर, मैं मानता हूं कि आयकर अधिकारी 'डी' वार्ड, हावड़ा द्वारा 7 फरवरी 1961 को पारित मूल्यांकन के आदेश इस हद तक गलत हैं कि वे निम्नलिखित कारणों से राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल हैं।

2. की गई पूछताछ से पता चला है कि रिटर्न में घोषित पते से कोई व्यवसाय नहीं किया गया था जैसा कि आरोप लगाया गया है। साथ ही उक्त आयकर अधिकारी द्वारा प्रारंभिक पूंजी, आभूषणों को अधिग्रहण और बिक्री, व्यवसाय से आय, आपके द्वारा दिये गये उपहार आदि को बिना किसी पूछताछ या सबूत के स्वीकार करना उचित नहीं था।

3. इसलिए, आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 33 बी के तहत मुझमें निहित शक्तियों के तहत आपको सुनवाई का अवसर देने के बाद मामलों की परिस्थितियाँ उचित आदेश पारित करने का प्रस्ताव करता है। मामलों की सुनवाई 1 फरवरी, 1963 को सुबह 11 बजे मेरे उपरोक्त कार्यालय में की जाएगी। जब आपसे अपने तर्कों के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। व्यक्तिगत सुनवाई

के लिए नियुक्ति पर या उससे पहले प्राप्त आवश्यक साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ लिखित आपत्तियों पर भी विधिवत विचार किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि सुनवाई में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

1 फरवरी, 1963 को निर्धारिती ने नोटिस जारी करने के खिलाफ आयुक्त के समक्ष विरोध जताया और कहा कि उक्त नोटिस कानून की दृष्टि से बिल्कुल खराब, अवैध और शून्य था। उसी तारीख को निर्धारिती ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 में एक प्रार्थना पत्र पेश किया अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई कि 24 जनवरी 1963 के उक्त नोटिस को रद्द कर दिया जाए या अलग रखा जाए और आयकर आयुक्त को उक्त नोटिस को प्रभावी करने से रोका जाए। याचिका पर बनर्जी, जे. ने सुनवाई की और उनके समक्ष तीन बिंदुओं का आग्रह किया गया।

(1) कि आयकर अधिनियम, 1922-इसके बाद 1922 अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है-आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निरस्त कर दिया गया है-इसके बाद इसे 1961 अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है- जो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ, आयकर आयुक्त के पास 1922 अधिनियम की धारा 33बी; के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं था।

(2) सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 किसी भी तरह से उक्त कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं देती है, क्योंकि जब 1922 अधिनियम लागू था और/या इसके निरसन से पहले इसके संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया था; और

(3) 1961 अधिनियम की धारा 298 के अधीन शक्तियों का प्रयोग केवल 1961 अधिनियम की धारा 297 द्वारा निपटाए गए मामलों के संबंध में किया जा सकता है। जो 1922 अधिनियम की धारा 33बी के तहत कार्यवाही से संबंधित नहीं है।

विद्वान न्यायाधीश के आधारों और निष्कर्षों की सराहना करने के लिए, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है।

"धारा 33बी (1922 अधिनियम) आयकर अधिकारी के आदेशों को संशोधित करने के लिए आयुक्त की शक्ति-(1) आयुक्त इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है और यदि वह मानता है कि आयकर अधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश गलत है, जहां तक यह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसी जांच करने या करवाने के बाद जो वह आवश्यक समझे कर सकता है। उस पर ऐसा आदेश पारित करें जो मामले की परिस्थितियों को उचित ठहराए, जिसमें मूल्यांकन को बढ़ाने या संशोधित करने, या मूल्यांकन को रद्द करने और नए मूल्यांकन का निर्देश देने वाला आदेश भी शामिल है।

(2) उपधारा (1) के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(ए) धारा 34 के प्रावधानों के तहत किए गए पुनर्मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करने के लिए; या

(बी) संशोधित किये जाने वाले आदेश की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद.....

(सी) "धारा 297. (1961 अधिनियम) निरसन और बचत। (1) 1922 का भारतीय आयकर अधिनियम 11, इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 का 11 (इसके बाद निरस्त अधिनियम के रूप में),- संदर्भित) के निरसन के बावजूद।

(ए) जहां किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के शुरू होने से पहले आय का रिटर्न दाखिल किया गया है, उस वर्ष के लिए उस व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए कार्यवाही की जा सकती है और जारी रखी जा सकती है जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

(बी) जहां 31 मार्च 1962 को या उससे पहले समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निरस्त अधिनियम की धारा 34 के तहत नोटिस के अनुसरण के अलावा इस अधिनियम के शुरू होने के बाद आय का रिटर्न दाखिल किया जाता है। किसी भी पूर्व वर्ष, उस वर्ष के लिए उस व्यक्ति का मूल्यांकन इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

(सी) किसी भी आयकर प्राधिकरण, अपीलीय-न्यायाधिकरण या किसी अदालत के समक्ष अपीलीय, संदर्भ या पुनरीक्षण के माध्यम से इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित कोई भी कार्यवाही जारी रखी जाएगी और निपटाया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था;

(डी) जहां 31 मार्च 1940 को समाप्त होने वाले वर्ष के बाद किसी मूल्यांकन वर्ष के संबंध में,-

(i) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले निरस्त अधिनियम की धारा 34 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, ऐसे नोटिस के

अनुसरण में कार्यवाही जारी रखी जा सकती है और निपटाया जा सकता है जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था;

(ii) कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय धारा 147 में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर मूल्यांकन से बच गई थी और ऐसी किसी भी आय के संबंध में निरस्त अधिनियम की धारा 34 के तहत कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ में लंबित नहीं है, धारा 148 के तहत एक नोटिस हो सकता है, धारा 149, या धारा 150 में निहित प्रावधानों के अधीन, उस मूल्यांकन वर्ष के संबंध में जारी किया जायेगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे;

(ई) निरस्त अधिनियम की धारा 23ए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में प्रभाव जारी रखेगी- 31 मार्च, 1962 या किसी भी पूर्व वर्ष को समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए कंपनी उसके शेयरधारकों को नियुक्त करती है और निरस्त अधिनियम के प्रावधान ऐसे मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू होंगे जैसे कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था;

(एफ) 1 अप्रैल, 1962 से पहले पूरे किए गए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में जुर्माना लगाने की कोई कार्यवाही शुरू की जा सकती है और ऐसा कोई जुर्माना लगाया जा सकता है जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।(जी) मार्च, 1962 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में जुर्माना लगाने की कोई कार्यवाही या किसी भी पूर्व वर्ष, जो '1 अप्रैल, 1962 को या उसके बाद पूरा हुआ हो सकता है।निरस्त अधिनियम के तहत किया

गया है और इस अधिनियम के तहत ऐसा कोई जुर्माना लगाया जा सकता है;

(एच) निरस्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरन्त पहले लागू किसी भी चुनाव या घोषणा या विकल्प का प्रयोग किसी निर्धारिती द्वारा किया गया चुनाव या घोषणा या विकल्प को संबंधित प्रावधान के तहत किया गया माना जाएगा।

(आई) जहां, इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले पूर्ण किए गए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में, ऐसे प्रारंभ के बाद रिफंड देय होता है या ऐसे पूर्ण मूल्यांकन के तहत देय किसी भी राशि के भुगतान में ऐसे प्रारंभ के बाद डिफ़ॉल्ट होता है, इस अधिनियम के प्रावधान संबंधित हैं रिफंड पर केंद्र सरकार द्वारा देय ब्याज और डी-फॉल्ट के लिए निर्धारिती द्वारा देय ब्याज लागू होगा;

(जे) निरस्त अधिनियम के तहत आयकर, सुपर-टैक्स, ब्याज, जुर्माना या अन्यथा के रूप में देय कोई भी राशि इस अधिनियम के तहत वसूल की जा सकती है, लेकिन निरस्त अधिनियम के तहत इस तरह की राशि की वसूली के लिए पहले से की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

(के) निरस्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किया गया कोई भी समझौता, नियुक्ति, मंजूरी दी गई, मान्यता दी गई, निर्देश, अनुदेश, अधिसूचना, आदेश या नियम जारी किया जाएगा। जब तक कि वह संबंधित प्रावधान के साथ असंगत न हो इस अधिनियम के

पूर्वोक्त संगत प्रावधान के तहत दर्ज किए गए, बनाए गए, दिए गए, दिए गए या जारी किया गया माना जाएंगा और तदनुसार लागू रहेंगे;

(एल) निरस्त अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) के तहत जारी और लागू कोई भी अधिसूचना इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले जिस सीमा तक इस अधिनियम के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, वह केंद्र सरकार द्वारा रद्द किए जाने तक लागू रहेगा।

(एम) जहां निरस्त अधिनियम के तहत किसी भी आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के लिए निर्धारित अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उससे पहले समाप्त हो गई थी, अधिनियम में कुछ भी ऐसे किसी भी आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन को सक्षम करने वाला नहीं माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत केवल इस तथ्य के आधार पर किया जाना चाहिए कि इसके लिए एक लंबी अवधि निर्धारित की गई है या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त मामलों में समय के विस्तार के लिए प्रावधान किया गया है।"

"धारा 298(1961 अधिनियम)। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:

(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधानों से असंगत कुछ भी कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या शीघ्र प्रतीत होता हों।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई भी आदेश उन अनुकूलन या संशोधनों के लिए प्रदान कर सकता है जिनके अधीन निरस्त अधिनियम 31 वें

दिन समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन के संबंध में लागू होगा। मार्च, 1962, या उससे पहले का कोई वर्ष।"

"धारा 6. (सामान्य-खंड अधिनियम)।

जहां यह अधिनियम, या कोई (केंद्रीय अधिनियम) या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाया गया विनियमन अब तक बनाये गये या इसके बाद बनाये जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, तो जब तक कि कोई भिन्न इरादा प्रकट न हो, निरसन नहीं होगा...

केंद्र सरकार ने धारा 298 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1962 जारी किया, जो 8 अगस्त, 1962 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। उक्त आदेश के खंड 2, 3 और 4 इस प्रकार पढ़े गए:

"2. पंजीकरण और रिफंड कार्यवाही को मूल्यांकन कार्यवाही का हिस्सा माना जाएगा:- आयकर अधिनियम, 1961 (43) की धारा 297 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) के प्रयोजनों के लिए 1961) (इसके बाद निरसन अधिनियम के रूप में संदर्भित), किसी फर्म के पंजीकरण या कर वापसी के दावे से संबंधित कार्यवाही को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए संबंधित व्यक्ति के मूल्यांकन की कार्यवाही का एक हिस्सा माना जाएगा।

3. निरसन अधिनियम की धारा 297(2)(बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों में मूल्यांकन पूरा करना- निरसन अधिनियम की धारा 297 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, मूल्यांकन अन्य बातों के साथ-साथ, निरसन अधिनियम की

निम्नलिखित धाराओं में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जहां तक वे इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं;

धारा 131 से 136, 140 से 146, 153 [उपधारा (3) की उपधारा (2) और खंड (iii) को छोड़कर], 156 से 158. 185, 187 से 189, 282 से 284 और 288।

4. निरस्त अधिनियम के तहत पारित आदेशों के संबंध में अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण कार्यवाही- (1) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत किए गए किसी भी आदेश के संबंध में पहली या बाद की अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से कार्यवाही। (बाद में इसे निरस्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को स्थापित और निपटाया जाएगा जैसे कि निरसन अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

(2) 31 मार्च 1962 के बाद और इस आदेश की तारीख से पहले निरसन अधिनियम के तहत शुरू की गई ऐसी कोई भी कार्यवाही निरस्त अधिनियम के तहत शुरू की गई मानी जाएगी और इसका निपटान इस तरह किया जाएगा जैसे कि निरसन अधिनियम पारित नहीं किया गया था;

बशर्ते कि यदि ऐसी कोई कार्यवाही निरसन अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत इस आदेश की तारीख से पहले निपटा दी गई है, तो इसे L9 Sup. Cl/67--13 के संबंधित प्रावधान के तहत निपटाया गया माना जाएगा और इस प्रकार निपटाई गई कार्यवाही के संबंध में किसी

भी अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण को स्थापित और निपटाया जाएगा जैसे कि निरस्त अधिनियम पारित नहीं किया गया था।"

विद्वान न्यायाधीश ने माना कि अभिव्यक्ति "मूल्यांकन के लिए कार्यवाही" धारा 1961 के अधिनियम के 297(2)(ए) का व्यापक अर्थ था और इसमें धारा के तहत कार्यवाही शामिल थी। 33 ए या धारा 1922 अधिनियम की धारा 33 बी. उन्होंने यह भी माना कि 1961 अधिनियम के 5. 297(2) के खंड (सी) और (डी) को अत्यधिक सावधानी के साथ अधिनियमित किया गया माना जाना चाहिए। अपने निष्कर्षों के मद्देनजर, उन्होंने यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा कि क्या धारा जनरल क्लॉज एक्ट के 6 एस के तहत शक्ति बचाई गई। 1922 अधिनियम का 33 बी, लेकिन उन्होंने देखा:

> "यदि ऐसा करना आवश्यक होता, तो मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि ऐसी शक्ति सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 खंड (सी) के तहत बचायी जायेगी और (ई) सामान्य खंड अधिनियम 1961 के निरसन अधिनियम में इसके विपरीत कोई संकेत नहीं है।"

उन्होंने तदनुसार याचिका खारिज कर दी।

निर्धारिती ने अपील की और डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी। डिवीजन बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि "मूल्यांकन के प्रावधान 1922 के अधिनियम के अध्याय IV में निहित हैं और धारा 33 बी इस अध्याय में जगह पाती है और अभिव्यक्ति "मूल्यांकन के लिए कार्यवाही" इंगित करती है कि मूल्यांकन से संबंधित कोई भी कार्यवाही अध्याय IV में विचार किया गया है, धारा 297 की उपधारा (2) के खंड (ए) के तहत शुरू और जारी रखा जा सकता है, जिसमें अधिनियम की धारा 33 बी के तहत

संशोधन के माध्यम से कार्यवाही भी शामिल है।" डिवीजन बेंच ने निर्धारिती के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सीएल। (सी) सीएल के दायरे को प्रभावित किया। (ए)। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सी.एल.धारा (डी) और (एफ) को अत्यधिक सावधानी के साथ शामिल किया गया था। इसने उस विवाद को भी खारिज कर दिया जो सी.एल. आयकर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1962 का (4) बुरा था, और देखा गया कि "खंड (4) ने जो किया है वह केवल यह स्पष्ट करना है कि खंड (ए) में क्या निहित था और यह उद्देश्य के साथ है धारा 297(2) के खंड (ए) के निर्माण के संबंध में मौजूद संदेह या कठिनाई, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए कि खंड (4) जैसा एक विशिष्ट प्रावधान कठिनाइयों को हटाने के आदेश में पेश किया गया था।" इन निष्कर्षों के मद्देनजर डिवीजन बेंच ने महसूस किया कि "इस बिंदु पर कोई निश्चित राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि क्या सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 6, 1961 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के उद्देश्य से उपलब्ध है। " परिणामस्वरूप खण्डपीठ के समक्ष अपील विफल रही और खारिज कर दी गई। निर्धारिती ने संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अपील अब हमारे सामने है।

निर्धारिती के विद्वान वकील का तर्क है कि धारा 297(2)(ए) में अभिव्यक्ति "मूल्यांकन के लिए कार्यवाही" 1961 के अधिनियम का अर्थ किसी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए मूल कार्यवाही है, न कि अपीलीय या पुनरीक्षण कार्यवाही। उनका कहना है कि संसद ने अपील और पुनरीक्षण के प्रश्न को एस के आवेदन द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया है। सामान्य खण्ड अधिनियम के 6. वह आगे कहते हैं कि "आकलन" शब्द का उपयोग इसके व्यापक अर्थ में नहीं किया गया है क्योंकि संसद ने सीएलएस में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। (एफ) और (जी), जो आम तौर पर "मूल्यांकन" के व्यापक अर्थ में आते हैं।

इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सीएल में लंबित कार्यवाही का क्या होगा। (सी) उनका आग्रह है कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि इन उपधाराओं को अत्यधिक सावधानी के कारण जोड़ा गया था।

प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री एस.टी.देसाई का मानना है कि धारा 297(2)(ए) धारा के तहत किसी भी कार्यवाही को शामिल करने के लिए अपने दायरे और आयाम में व्यापक है। 1922 अधिनियम की धारा 33 बी. वह आगे कहते हैं कि धारा सामान्य धारा अधिनियम के 6 उस सीमा तक लागू होंगे जहां धारा में कोई विपरीत इरादा न हो। 1961 अधिनियम की धारा 297(2)। उन्होंने अंततः तर्क दिया कि भले ही सीएल के दायरे के संबंध में कोई संदेह हो। (ए) इसे एस के तहत जारी कठिनाइयों को हटाने के आदेश द्वारा हटा दिया गया है। धारा 298.

हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि 1961 के अधिनियम की धारा 297(2)(ए) में इसके दायरे में धारा के तहत कार्यवाही शामिल है। 1922 अधिनियम की धारा 33 बी. इसमें कोई संदेह नहीं है कि "आकलन" शब्द का संदर्भ के अनुसार बहुत व्यापक अर्थ है। आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम खेमचंद रामदास मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा: "उन्हें उत्तर देने के लिए कर का आकलन करने के लिये अधिनियम द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखना जिसके करदाता पर दायित्व थोपने की पूरी प्रक्रिया को शामिल करते हुए इसके व्यापक अर्थ में आवश्यक है।

मूल्यांकन शब्द का उपयोग किया जाता है,

ए.एन. लक्ष्मण शेनॉय बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम (2) में इस न्यायालय ने कहा:

> "अब सवाल यह है कि वित्त अधिनियम, 1950 की धारा 13(1) में "मूल्यांकन" शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया गया है। दो

परिस्थितियों पर एक साथ ध्यान दिया जा सकता है। लंबे शीर्षक में कहा गया है कि वित्त अधिनियम, 1950, 1 अप्रैल, 1950 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए अधिनियम है और धारा 13 (1) में शब्दों का संयोजन

"आय का आरोपण, मूल्यांकन और संग्रहण है-"

(1) 61 आई.टीआर. 414 पृष्ठ 423 पर। (2) 34 आई.टी.आर. 275 पी. 291

कर हमारी राय में, ये दोनों परिस्थितियाँ एक व्यापक अर्थ की ओर इशारा करती हैं; क्योंकि केंद्र सरकार के प्रस्ताव के हिस्से के रूप में, यह इरादा नहीं किया जा सकता था कि जिनकी आय पूरी तरह से मूल्यांकन से बच गई है, उन्हें उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन जो कम मूल्यांकन को बरी कर दिया जाना चाहिए। हम अनुभाग के शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं देख सकते हैं जो इस तरह के अंतर को उचित ठहरा सके; हम इस तर्क से बिल्कुल अलग कहते हैं कि धारा 13 (1) की व्याख्या वित्ततीय समझौते के अनुरूप की जानी चाहिए राजप्रमुख और राष्ट्रपति के बीच हुआ वित्तीय समझौता, एक तर्क जिस पर हम वर्तमान में चर्चा करेंगे। इसके अलावा, "लेवी, मूल्यांकन और संग्रह" शब्दों का संयोजन इंगित करता है कि इसका मतलब पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर का पता लगाया जाता है माँग की जाती है और साकार किया गया।"

सी. ए. अब्राहम बनाम आयकर अधिकारी, कोट्टायम में इस न्यायालय ने कहा:

"अधिनियम के अध्याय IV के प्रावधानों की समीक्षा से पर्याप्त रूप से पता चलता है कि "मूल्यांकन" शब्द का उपयोग उस अध्याय में इसके व्यापक अर्थ में किया गया है। अध्याय का शीर्षक "कटौती और मूल्यांकन" है। वह धारा जो केवल आय की गणना के रूप में मूल्यांकन से संबंधित है धारा 23 है; लेकिन कई धाराएं आय की गणना से नहीं, बल्कि देनदारी के निर्धारण, देनदारी लगाने की मशीनरी और उस संबंध में प्रक्रिया से संबंधित हैं। धारा 18 ए कर के अग्रिम भुगतान और उसके प्रावधानों को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित है। धारा 23 ए लाभांश के रूप में वितरित की गई आय पर कुछ कंपनियों के व्यक्तिगत सदस्यों का आकलन करने की शक्ति से संबंधित है, धारा 23 बी कर योग्य क्षेत्रों से प्रस्थान के मामले में मूल्यांकन से संबंधित है, धारा 24 बी मृत व्यक्तियों की संपत्ति से कर की राशि संग्रह से संबंधित है, धारा 25 बंद किए गए व्यवसाय के मामले में मूल्यांकन से संबंधित है, धारा 25 ए हिंदू अविभाजित परिवारों के विभाजन के बाद मूल्यांकन से संबंधित है और धारा 29, 31, 33 और 35 नोटिस जारी करने और अपील दाखिल करने और मूल्यांकन की समीक्षा करने के लिए और धारा 34 उन आय के मूल्यांकन से संबंधित है जो मूल्यांकन से बच गई हैं। इन धाराओं में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मूल्यांकन" का उपयोग केवल आय की गणना के अर्थ में नहीं किया जाता है और हमारे निर्णय में यह मानने का कोई आधार नहीं है कि जब धारा 44 द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि एसोसिएशन के भागीदार या सदस्य संयुक्त रूप से होंगे और मूल्यांकन के लिए अलग से उत्तरदायी है इसका उद्देश्य केवल

घोषित करने का इरादा है। (1)41 आई.टी.आर. 425 पृष्ठ 429-430 पर।

धारा 23 के तहत आय की गणना के लिए दायित्व, न कि कर दायित्व की घोषणा और लगाने की प्रक्रिया के आवेदन और उसके प्रवर्तन के लिए मशीनरी के लिए।"

आयकर आयुक्त बनाम भीकाजी दादाभाई एंड कंपनी(1) में इस न्यायालय ने अब्राहम बनाम आयकर अधिकारी(2) में "मूल्यांकन" शब्द के संबंध में टिप्पणियों को मंजूरी के साथ उद्धृत किया।

आयकर आयुक्त बनाम पड्याला सीमेंट कंपनी लिमिटेड(3) में भी इसी तरह का प्रश्न उठा था। सवाल यह था कि क्या वित्त अधिनियम, 1950 की धारा 13 आकलन के संबंध में अपील के तहत 1949-50 के द्वारा शासित किया जाएगा। पटियाला आयकर अधिनियम, 2001, या भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा हम यहां वित्त अधिनियम, 1950 की धारा 13 निर्धारित कर सकते हैं:

"यदि 1 अप्रैल, 1950 से ठीक पहले, जम्मू-कश्मीर या मणिपुर, त्रिपुरा या विंध्य प्रदेश के अलावा किसी भाग बी राज्य में या कूच-बिहार के विलय वाले क्षेत्र में आयकर से संबंधित कोई कानून लागू है या सुपर-टैक्स या व्यापार के मुनाफे पर कर, उस कानून का प्रभाव पिछले वर्ष में शामिल नहीं की गई किसी भी अवधि के संबंध में आयकर और सुपर-टैक्स के आरोपण, मूल्यांकन और संग्रह के उद्देश्यों को छोड़कर बंद हो जाएगा। 31 मार्च 1951 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, या किसी भी बाद के वर्ष के लिए, या, जैसा भी मामला हो, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का XI) के तहत कर निर्धारण, कर

निर्धारण और संग्रहण 31 मार्च, 1949 को या उससे पहले समाप्त होने वाली किसी भी प्रभार्य लेखांकन अवधि के लिए व्यापार के मुनाफे पर कर।"

इस न्यायालय ने माना कि यह पटियाला अधिनियम 2001 के प्रावधान हैं जो लागू होते हैं। इस बात का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया कि किसी भी स्थिति में जब पटियाला अधिनियम का प्रभाव समाप्त हो गया, तो अपील से निपटने वाले प्रावधानों कर लगाने, मूल्यांकन और आयकर के संग्रह से कोई संबंध नहीं था।

भाईलाल अमीन एंड संस लिमिटेड बनाम आर.पी. दलाल (4) में बॉम्बे हाई कोर्ट (छागला, सी.जे., और शाह जे.), ने कराधान कानून (विलयित राज्यों का विस्तार और संशोधन) अधिनियम (1949 का LXVII) की धारा 7 की व्याख्या की। जिसका प्रासंगिक भाग निम्नलिखित शर्तों में है:

7. (1) यदि, 26 अगस्त 1949 से ठीक पहले, विलय किए गए किसी भी राज्य में आयकर, सुपर-टैक्स, या व्यापार लाभ कर से संबंधित कोई भी कानून लागू था तो वह कानून समाप्त हो जाएगा पृष्ठ 127 पर प्रभाव

(1) 42 आई.टी.आर. 123 पी

(2) 41 आई.टी.आर. 425

(3) 32 आई.टी.आर. 333.

(4) 24 आई.टी.आर. 229

आयकर और किसी भी अवधि के संबंध में आरोपण, मूल्यांकन और संग्रह के उद्देश्यों को छोड़कर, सुपर-टैक्स के तहत मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए पिछले वर्ष में शामिल नहीं किया है। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 जैसा कि धारा 3 द्वारा उस

राज्य तक विस्तारित है या, जैसा भी मामला हो, 31 मार्च, 1948 को या उससे पहले समाप्त होने वाली किसी भी प्रभार्य लेखांकन अवधि के लिए व्यापार लाभ कर का उद्ग्रहण, मूल्यांकन और संग्रह, और इस तरह के लेवी, मूल्यांकन या संग्रह से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए...

> "याचिकाकर्ताओं के लिए श्री पालकीवाला द्वारा यह आग्रह किया गया है कि शब्द "लेवी, मूल्यांकन और संग्रह" लागू नहीं होता है। इसमें मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार शामिल नहीं है और बड़ौदा कानून अपील के किसी भी अधिकार पर लागू नहीं होता है, जो याचिकाकर्ताओं के पास मूल्यांकन के आदेश के संबंध में हो सकता है। पहली बार में यह तर्क मुझे बिल्कुल सही लगता है निरर्थक तर्क है, क्योंकि यदि मुझे अनुभाग के बारे में ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया तो यह याचिकाकर्ताओं को अपील के किसी भी अधिकार के बिना छोड़ देगा। यदि बड़ौदा अधिनियम लागू होना बंद हो जाता है और स्पष्ट रूप से भारतीय अधिनियम लेखांकन वर्ष 1948-49 से पहले के लेखांकन वर्षों के आकलन पर लागू नहीं होता है, तो अपील का कोई अधिकार नहीं है; और याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल मे जा नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसी कोई अन्य धारा या अनुभाग नहीं है जो भारतीय आयकर अधिनियम के तहत अपील का कोई अधिकार प्रदान करता हो बड़ौदा अधिनियम के तहत किये गये आकलन के संबंध में लेकिन, इसके अलावा, मेरी राय में आयकर के उद्ग्रहण, मूल्यांकन और संग्रहण की सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, क्योंकि प्रक्रिया के बिना कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है या संग्रह और विशेष रूप से "आकलन" को ध्यान में

रखते हुए, जिसके साथ हम इस याचिका पर चिंतित हैं, मूल्यांकन तब तक अंतिम नहीं है जब तक कि अधिनियम द्वारा दिए गए अपील के माध्यम से सभी उपचार समाप्त नहीं हो जाते। इस दृष्टिकोण पर उप-धारा (1) के अंतिम शब्दों द्वारा जोर दिया गया है जो "इस तरह के लेवी, मूल्यांकन और संग्रह के संबंध में किसी भी उद्देश्य के लिए हैं।" किसी भी घटना में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपील के अधिकारों सहित मूल्यांकन की प्रक्रिया "मूल्यांकन से जुड़े उद्देश्यों" शब्दों में शामिल है। मेरी राय में। इसलिए। धारा 7 की उप-धारा (1) का वास्तविक अर्थ यह है कि बड़ौदा अधिनियम याचिकाकर्ताओं के मूल्यांकन पर लागू होता है, यहां तक कि अपील के अधिकार के संबंध में भी जो उस अधिनियम के तहत हुज़ूर अदालत को दिया गया था।"

ऊपर उद्धृत अधिकारियों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि "आकलन" शब्द का बहुत व्यापक अर्थ हो सकता है: यह करदाता पर दायित्व का पता लगाने और लगाने की पूरी प्रक्रिया को समझ सकता है। तो क्या एस के सन्दर्भ में कोई बात है? धारा 297 का संदर्भ जो हमें अभिव्यक्ति "मूल्यांकन की प्रक्रिया" को अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए संकीर्ण अर्थ देने के लिए मजबूर करता है? हमारे विचार में, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि धारा 297 का उद्देश्य उन सभी आकस्मिकताओं के लिए यथासंभव प्रावधान करना है जो 1922 अधिनियम के निरसन से उत्पन्न हो सकती हैं। यह लंबित अपीलों, संशोधनों आदि से निपटता है। यह 1961 अधिनियम के प्रारंभ में लंबित अपूर्ण मूल्यांकन और (सी) 1961 अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद दायर किए गए आय के रिटर्न के परिणामस्वरूप किए जाने वाले आकलन से संबंधित है। 1961 अधिनियम की शुरूआत. फिर सीएल में. (डी) यह बची हुई आय के संबंध में आकलन से संबंधित है; सीएलएस में. (एफ) और (जी) यह जुर्माना लगाने

से संबंधित है; सी.एल. (ज) 1922 अधिनियम के तहत किए गए चुनावों या घोषणाओं का प्रभाव जारी रहेगा; सी.एल. (i) रिफंड से संबंधित है; सी.एल. (जे) वसूली से संबंधित है; सी.एल. (के) आम तौर पर 1922 अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी समझौतों, अधिसूचनाओं, आदेशों से संबंधित है; सी.एल. (1) एस के तहत जारी अधिसूचना जारी है। 1922 अधिनियम की धारा 60(1) और सी.एल. (एम) कुछ आवेदनों, अपीलों आदि के लिए 1961 अधिनियम के तहत निर्धारित लंबी अवधि की सीमा के आवेदन के खिलाफ सुरक्षा करता है। इस संदर्भ में यह शायद ही विश्वसनीय है कि संसद ने पहलू से किये गये मूल्यांकन आदेशों के संबंध में अपील और संशोधन के बारे में नहीं सोचा था या जिन्हें सीएल के तहत बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। (ए) का धारा 297(2).

अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि संसद ने धारा 6 सामान्य खंड अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, और इसलिए अपील और संशोधन आदि से निपटने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाया था। हमारे विचार में, एस। सामान्य धारा अधिनियम के 6 लागू नहीं होंगे क्योंकि धारा 297 (2) इसके विपरीत इरादे का सबूत देता है। भारत संघ बनाम मदन गोपाल काबरा (1) में धारा की व्याख्या करते हुए। वित्त अधिनियम, 1950 का 13 जो पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है, इस न्यायालय ने पृष्ठ पर देखा 68:

> "न ही सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 6, वर्ष 1949-50 की आय पर कर का भुगतान करने के दायित्व को जीवित रखने के लिए काम कर सकती है, यह मानते हुए कि यह बार-बार राज्य कानून के तहत अर्जित हुआ है, एक "अलग इरादे" के लिए स्पष्ट रूप से प्रकट होता है जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्त अधिनियम की धारा 2 और 13 को एक साथ पढ़ा जायेगा।"

यह सच है कि कोई अलग इरादा प्रकट होता है या नहीं, यह धारा 297(2). की भाषा और सामग्री पर निर्भर होना चाहिए। हालाँकि, हमें ऐसा लगता है कि ऊपर उल्लिखित इतने सारे मामलों को प्रदान करने से, कुछ इसके अनुरूप परिणाम होगा।

(1) 25 आई.टी.आर. 58.

सामान्य अधिनियम की धारा 6 और कुछ इसके विपरीत कि धारा के तहत परिणाम क्या होगा। संसद ने स्पष्ट रूप से इसके विपरीत इरादे का प्रमाण दिया है।

यदि धारा सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6 रास्ते से बाहर है इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1922 अधिनियम के तहत किए गए मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध अपील और संशोधन आदि का प्रावधान न करने के इरादे का श्रेय संसद को नहीं दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, उस व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए कार्यवाही अभिव्यक्ति देनी चाहिए जिसका बहुत व्यापक अर्थ है। किसी भी दर पर, यदि आयकर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1962 वैध है, तो उक्त आदेश का पैरा 4 स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले को कवर करता है और आयुक्त को विवादित नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र देगा।

जालान ट्रेडिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम मिल मजदूर यूनियन (1) पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 298 शून्य है. हमारे विचार में, वर्तमान मामला आयकर आयुक्त बनाम दीवान बहादुर रामगोपाल मिल्स (2) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया है, जहां कराधान कानून के समान आदेश (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1950 वित्त अधिनियम, 1950 के 12 के तहत बनाये गये भाग बी राज्य को बरकरार रखा गया। धारा 12 इस प्रकार पढ़ी गई:

> "यदि धारा 3 या धारा II द्वारा किसी राज्य या विलय किए गए क्षेत्र में विस्तारित किसी भी अधिनियम, नियम या आदेश के प्रावधानों को

प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकती है, या ऐसा निर्देश दे सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।"

न्यायालय की ओर से बोलते हुए एस. के. दास, जे., पृष्ठ पर टिप्पणी की 288:

"इसके अलावा, धारा 12 का वास्तविक दायरा और प्रभाव यह प्रतीत होता है कि यह केंद्र सरकार का काम है कि वह यह निर्धारित करे कि धारा में संकेतित प्रकृति की कोई कठिनाई उत्पन्न हुई है या नहीं और फिर ऐसा आदेश दे, या ऐसा निर्देश दे, जैसा प्रतीत हो कठिनाई को दूर करना आवश्यक है। संसद ने मामले को कार्यपालिका पर छोड़ दिया है; लेकिन इससे 1956 की अधिसूचना ख़राब नहीं हो जाती। पंडित बनारसी दास भनोट बनाम मध्य प्रदेश राज्य (3) में हमने पृष्ठ पर कहा था। 435: "अब, अधिकारियों को स्पष्ट हैं कि कराधान कानूनों के कामकाज से संबंधित विवरण निर्धारित करने के लिए विधायिका के लिए इसे कार्यपालिका पर छोड़ना असंवैधानिक नहीं है, जैसे कि उन व्यक्तियों का चयन जिन पर कर लगाया जाना है। वे दरें जिन पर विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं आदि के संबंध में शुल्क लिया जाना है।" इसलिए, हम हैं।

(1) [1966] 11 एल.एल.जे. 546.

(2)41 आई.टी.आर. 281.

(3) 9 एस.टी.सी. 388.

इस विचार से कि 1956 की अधिसूचना वैध रूप से धारा 12 के तहत बनाई गई थी और उस धारा द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अधिकार के बाहर नहीं है।

यह सच है कि उस मामले में हमला अधिसूचना पर था न कि धारा पर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि न्यायालय द्वारा दिया गया अनुपात धारा की वैधता को कवर करने के लिए उचित है। इसके अलावा, एस की शर्तें। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के 37 अलग हैं और बोनस अधिनियम कोई कर लगाने वाला कानून नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और जुर्माने सहित खारिज कर दी जाती है।

आर.के.पी.एस अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक डॉ. मुकेश कुमार (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।